डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 22 ● भोपाल ● 16-30 अप्रैल, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

सरकार का गरीब कल्याण एजेण्डा

सभी को मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्वालियर में ''दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना'' का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महान चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश सरकार गरीब कल्याण एजेण्डा बनाकर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक दिलवाने के लिये कृत-संकल्पित है। इसी कड़ी में प्रदेश में गरीब-मजदूरों को पाँच रूपए में भरपेट भोजन देने की महत्वाकांक्षी ''दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना'' का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्वालियर में योजना का शुभारंभ कर रहे थे।

कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। इसी भावना से सभी जिलों में एक साथ दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ सामाजिक सहभागिता से किया जा रहा है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गरीब मजदूरों को पाँच रूपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। गाँव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवासीय पट्टा और शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को आवास बनाकर देने का काम सरकार बहुत तेजी से कर रही है।

श्री चौहान ने शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि अब सरकार ऐसे सभी छात्र जो 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे और जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉली-टेक्निक, लॉ आदि की शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनकी फीस भरने का काम सरकार करेगी। इसके लिये बजट में एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रति वर्ष बढ़ाया जायेगा। अगले पाँच वर्ष में इस मद में पाँच हजार करोड़ रूपए तक का प्रावधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो बेटा-बेटी विदेश में शिक्षा के लिये जायेंगे, उनकी फीस देने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। श्री चौहान ने गरीबों के लिये स्वास्थ्य, रोजगार सहित अन्य क्षेत्र में चलाई जा रहीं जन-हितकारी योजनाओं की भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में योजना का संचालन करने वाली वैश्य महासभा को बधाई देते हुए योजना में सहभागी बनने के लिये राज्य सरकार की ओर से आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जन-कल्याण के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अब दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना भी जुड़ गयी है।

श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की कर्मठता और काम के प्रति लगन का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर विकसित राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बना सका है। उन्होंने प्रदेश में हो रहे नवाचारों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक अप्रैल से सभी नगरीय निकायों को ई-नगर पालिका से जोड़ दिया गया है। श्रीमती सिंह ने योजना के शुभारंभ के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि प्रदेश के सभी स्थान पर योजना जन-अकांक्षाओं पर खरी उतरे।

मुख्यमंत्री ने परोसा भोजन

मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करने के बाद रसोई घर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भोजन कर रहे लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
ई-8/77,शाहपुरा, भोपाल
फोन 0755-2726160, 2725518 फैक्स 2726160
e-mail: mpscu.bpl@mp.gov.in website: www.mpscu.in

हायर डिप्लोमा इन को-आपरेटिव्ह मैनेजमेंट (HDCM) में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में दिनांक 25 अप्रेल 2017 से 20 सप्ताह की अवधि के सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (**HDCM**)में प्रवेश हेतु स्वाध्यायी/संस्थागत/विभागीय प्रशिक्षणार्थियों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पाठ्यक्रम शुल्क रूपये 6000/- है। (अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी)। अभ्यर्थी 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर के प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जायगी। पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर से संबंधित विषय भी सम्मिलित है।
आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क करें-

1. सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल दूरभाष 0755-2725518 मो. 9425377233
2. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैदान इन्दौर दूरभाष 0731- 2410908 मो. 9826031440
3. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हनुमानताल जबलपुर दूरभाष 0761-2341338 मो.9424782856
4. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर दूरभाष 07685-256344 मो. 9407060480

प्रबंध संचालक

प्रदेश में इस वर्ष गरीबों के लिये बनेंगे 10 लाख आवास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दमोह में 355 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में गरीबों के लिये 10 लाख आवास बनाये जायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करवायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान दमोह में अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया और दमोह जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले मौजूद थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंत्योदय मेले में 355 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में 50 हजार हितग्राही को 19 हजार 426लाख रुपये की सहायता राशि के चेक वितरित किये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिये राज्य सरकार ने एजेंडा तैयार किया है। राज्य में करीब 5 करोड़ 50 लाख व्यक्ति को एक रुपये किलो पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह को आर्थिक मदद, पंचायत एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, शिक्षकों के पद पर 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को जल्द ही नशा-मुक्त बनाया जायेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शराब के साथ तम्बाखू का सेवन भी छोड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल से प्रदेश में **ग्रामोदय से भारत उदय** अभियान चलाया जायेगा। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामसभा होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन **ग्रीन दमोह** की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले का प्रत्येक नागरिक एक पौधा लगाये और गाँव में एक तालाब तैयार करने का संकल्प ले।

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि पिछले वर्ष 9 तालाब का जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने कहा कि दमोह सामाजिक सरोकार के कामों में हमेशा आगे रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 29 अप्रैल को दमोह में सामूहिक विवाह समारोह रखा गया है।

समारोह में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 1000 जोड़ों का विवाह करवाया जायेगा। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि दमोह में 13 किलोमीटर का बायपास तैयार हो गया है।

शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1850 मकान नगरपालिका द्वारा और 950 आवास अटल आश्रय योजना में तैयार किये जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 45 करोड़ की लागत से जुझार-घाट पेयजल परियोजना में टंकी निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। शहर में पाइप-लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पंचम नगर सिंचाई योजना पूर्णता की ओर है। इससे 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कन्याओं का पूजन किया और उन्हें उपहार भेंट किये। उन्होंने **नमामि देवि नर्मदे** की प्रस्तुति देने वाले अनहद कला केन्द्र के बाल कलाकारों और जेपीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को 25-25 हजार की राशि भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंत्योदय मेले में पहुँचने पर स्वागत से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि दैनिक भास्कर के चेयरमेन श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल का आकस्मिक निधन हो गया है। श्री अग्रवाल सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने श्री अग्रवाल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

किसानों को मिले 45003 करोड़ के सहकारी ऋण

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का रिकार्ड 339.51 लाख मी. टन उत्पादन

भोपाल। मध्यप्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करते हुए इस साल भी रिकार्ड बनाया है। गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दालों का उत्पादन बढ़ा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015-16में 45003 करोड़ 25 लाख का सहकारी कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16में बढ़कर 339 लाख 51 हजार मीट्रिक टन हो गया है। यह वर्ष 2014-15 के मुकाबले 18.35 प्रतिशत तक बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 286लाख 87 हजार मीट्रिक टन था। इसी प्रकार गेहूँ उत्पादन में वर्ष 2014-15 के मुकाबले इस साल 7.64 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2014-15 में गेहूँ का उत्पादन 171 लाख 03 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2015-16में बढ़कर 184 लाख 10 हजार मीट्रिक टन हो गया है। चावल का उत्पादन भी 36लाख 25 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 53 लाख 20 हजार मीट्रिक टन हो गया है।

किसानों की लगन और कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कृषि विभाग के मैदानी अमले के मिले-जुले प्रयास से यह उपलब्धि हासिल हुई है।

45,003 करोड़ के कृषि ऋण

किसानों को बेहतर साख सुविधा देने के लिए उठाये गए कदमों के निरंतर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015-16में 45003 करोड़ 25 लाख का सहकारी कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया, जो वर्ष 2014-15 में उपलब्ध करवाए गए कृषि ऋण 36583 करोड़ 18लाख से 8420 करोड़ 07 लाख ज्यादा है।

दलहन उत्पादन में सर्वोत्तम प्रदर्शन

दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश ने सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। वर्ष 2014-15 में दालों का उत्पादन 48 लाख 28 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2015-16में बढ़कर 56 लाख 54 हजार मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले 17.11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। मोटे अनाज का उत्पादन भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में मोटे अनाज का उत्पादन 31 लाख 29 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2015-16में बढ़कर 45 लाख 67 हजार मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार पिछली बार के मुकाबले 45.96प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी

खेती करने की सर्वोत्तम विधियाँ अपनाने से खाद्यान्न उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हुई है। अब यह बढ़कर 2183 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। पिछली बार वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादकता 1856 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इसी प्रकार गेहूँ की उत्पादकता बढ़कर 3115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। पिछले साल यह 2850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। दालों की उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2015-16 में 980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है जो वर्ष 2014-15 में 876 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इस प्रकार 11.87 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों को कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें सिंचाई, विद्युत, तकनीकी परामर्श, ब्याज रहित ऋण, मंडी प्रांगण में उपार्जन की ई-सुविधा मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी साबित हुई है।

राज्य सहकारी संघ : प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्राचार्य, व्याख्याताओं एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कला में अद्यतन करने के लिये मुख्यालय में २ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रशिक्षकों का मुख्य कार्य प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण कार्य में नवीन तकनीक का उपयोग होने लगा है जिससे प्रशिक्षण प्रभावकारी व सार्थक होता है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण में इस तकनीक का ज्ञानार्जन प्राप्त होगा। आपने आशा व्यक्त की प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्य में प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करेंगे तभी प्रशिक्षण सार्थक होगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री पृथ्वीराज सिन्हा ने प्रशिक्षकों को संचार का महत्व, प्रशिक्षण की नवीन विधियों, तकनीक के साथ ही व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

बंजर जमीन पर बिना बीज की ककड़ी

नीमच जिला बना सामूहिक संरक्षित खेती का अभिनव उदाहरण

भोपाल। नीमच जिले के 30 किसान ने 100 बीघा बंजर जमीन को सामूहिक एवं संरक्षित खेती की सोच के साथ उपजाऊ बनाया है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से लगे सेमार्डा गाँव के नजदीक पहाड़ीनुमा बंजर जमीन पर पॉली-हाउस तैयार कर ककड़ी लगायी। अब यहाँ पैदा हुई ककड़ी विदेशों में निर्यात की जा रही है।

खेती-किसानी में रुचि रखने वाले युवा किसान अनिल नाहटा, शौकीन जैन, संजय बेगानी और सत्यनारायण पाटीदार कुछ समय पहले इंटरनेशनल फूड एक्जीविशन में दुबई गये थे। वहाँ उन्होंने देखा कि 50 डिग्री तापमान से अधिक गर्म रेत पर सब्जियाँ और फलों की खेती की जा रही है। उन्होंने इस तकनीक को बारीकी से देखा। नीमच आते ही उन्होंने बंजर जमीन को समतल करने का जतन शुरू किया और 6पॉली-हाउस तैयार किये। इसके बाद इसी भूमि पर 32 पॉली-हाउस और तैयार किये गये। केवल 3 माह में हाइड्रोपॉनिक पद्यति से बिना बीज की हरी ककड़ियों ने आकार लेना शुरू कर दिया।

बिना बीज की ककड़ी की माँग बढ़ी

सउदी अरब में बिना बीज की ककड़ी की हमेशा डिमांड बनी रहती है। नीमच जिले में तैयार बिना बीज की ककड़ी की खेप दिल्ली की मण्डियों तक पहुँच गयी है। बाद में यह ककड़ी अरब के बाजारों में पहुँचेगी। एक पॉली-हाउस में 70 टन ककड़ी का उत्पादन हो रहा है। एस.एन. नेचर फ्रेश के जनरल मैनेजर डॉ. संतोष सिंह ने बताया कि बीज-रहित ककड़ी का दाम 20 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। यहाँ के किसान अब पॉली-हाउस में खूबसूरत फूलों की खेती करने का भी विचार कर रहे हैं। यहाँ पैदा होने वाले जरबेरा रोज की क्षेत्रीय बाजार के साथ जर्मनी और हॉलेण्ड में भी बड़ी माँग है।

ड्रिप पद्यति से ऑटोमेटिक सिंचाई

इस पद्धति की विशेषता यह है कि आधुनिक खेती के लिये पानी और बिजली की अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। ट्यूब-वेल लगाकर उसके पास ढलान में 12 हजार लीटर क्षमता का अंडरग्राउण्ड वॉटर-टैंक बनाया गया है। वर्तमान जरूरत के मान से प्रतिदिन 6लाख लीटर पानी की खपत हो रही है। इसमें हर पॉली-हाउस तक पाइप-लाइन बिछाकर हाउस के अंदर जहाँ-जहाँ पौधे के कॉकपिट हैं, वहाँ तक पाइप जोड़कर पानी पहुँचाया गया है। इसमें टपक सिंचाई प्रक्रिया से पौधे की जड़ों को हमेशा नम रखा जाता है। किस डोम में कितना पानी पहुँचाना है, इसकी भी कम्प्यूटराइज व्यवस्था की गई है।

संचालक श्री शौकीन जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप खेती को लाभ का धंधा ही नहीं, बल्कि उद्योग का दर्जा दिलवाने की यह कोशिश है। जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ के किसान सामूहिक संरक्षित खेती करने में सफल रहे हैं। पथरीली जमीन पर की गयी खेती को देखने सैलाना एवं सेंधवा के किसान भी पहुँचे और उन्होंने भी इस तकनीक का अध्ययन किया।

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना
हर साल ढाई लाख युवा होंगे प्रशिक्षित

भोपाल। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में हर साल 2 लाख 50 हजार युवा को प्रशिक्षित किया जायेगा। योजना में ऐसे प्रशिक्षण दिये जायेंगे, जिनकी पूर्ति परम्परागत आईटीआई पाठ्यक्रमों से संभव नहीं है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने बताया कि योजना में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ चुके युवा कामगार, जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो अपने कौशल को बढ़ाकर स्व-रोजगार करना चाहते हैं, को प्राथमिकता दी जायेगी। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। युवाओं को परिधान एवं गृह स%जा, आटोमोबाइल्स, केपिटल गुड्स, वुडवर्क, टेक्नीशियन, निर्माण, घरेलू काम-काज, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, कृषि, ग्रीन जॉब, प्लंबर, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, आई.टी. सुरक्षा, टेलीकॉम, टूरि%म एण्ड हास्पिटेलिटी एवं वित्त सेवा से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा में 42 करोड़ स्वीकृत

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दतिया जिले में 23 हजार 102 किसानों को वितरण के लिए 42 करोड़ 11 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। शीघ्र ही यह राशि वितरित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दावा राशि भुगतान में दतिया जिला न केवल प्रदेश में अपितु पूरे देश में अव्वल है। इसके पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने पिछले नवम्बर माह में 16 हजार 260 किसानों को 9 करोड़ 39 लाख रूपये की राशि अंतरिम दावे के रूप में बाँटी थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2016में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी। योजना के अंतर्गत अंतरिम राशि दावा भुगतान में दतिया जिला अव्वल रहा था और अब अंतिम दावा राशि भुगतान में भी अव्वल हो रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने किसान वर्ग के प्रति संवेदनशील रहकर आपदा की स्थिति में उनकी सहायता की है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान और जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र निरंतर प्रयासरत रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर दतिया कलेक्टर श्री मदन कुमार भी तत्पर रहे हैं। फसल बीमा योजना में राहत राशि के वितरण कार्यक्रम में किसानों ने भी इस बात की तारीफ की थी। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को जानकारी मिली कि दतिया जिले के किसानों की खरीफ की फसल को नुकसान पहुँचा है तो उन्होंने कलेक्टर श्री मदन कुमार को तत्परता से सर्वे कार्य कराने के निर्देश दिए। पटवारियों तथा राजस्व अधिकारियों ने कृषि विभाग और बीमा कंपनी के साथ गाँव-गाँव जाकर फसल सर्वे किया और नुकसानी का आकलन किया। फसलों में हुए नुकसान के आधार पर अंतरित दावा भुगतान के रूप में 9 करोड़ से अधिक की राशि 4 नवम्बर 2016को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने स्वयं दतिया आकर वितरित की थी।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

15 अप्रैल से 2 मई तक कृषि महोत्सव

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। प्रदेश में 14 अप्रैल से 31 मई तक चार चरण में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चलेगा और 15 अप्रैल से 2 मई तक कृषि महोत्सव मनाया जायेगा। इसके लिये सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। ग्रामोदय अभियान का शुभारंभ डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर उनकी स्मृति को नमन करने के साथ होगा। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। तीसरा चरण 1 मई से 21 मई और चौथा चरण 22 मई से 31 मई तक चलेगा। जिलों के प्रभारी मंत्री इस अभियान की शुरूआत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में तैयारियों की समीक्षा करते हुए हर गाँव में जल का कम से कम एक स्त्रोत विकसित करने या जीवित करने पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वसहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की रणनीति बनाने के भी निर्देश दिये।

ग्राम संसदों का आयोजन

अभियान के दौरान ग्राम संसदों का आयोजन किया जायेगा। अधोसंरचना विकास, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना के

हितग्राहियों का चयन, अभियान की गतिविधियों की समीक्षा और कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी। पिछले साल सफलतापूर्वक संपन्न ग्रामोदय अभियान में उत्कृष्ट काम करने वाले जिला कलेक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरुस्कृत किया जायेगा। अभियान में राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से गतिविधियां क्रियान्वयित की जायेंगी। ग्राम संसदों में कृषि आय को दोगुनी करने की कार्ययोजना पर चर्चा होगी और इसे अंतिम रूप दिया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं समृद्धि से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं में अगले दो वर्ष की कार्ययोजनाएँ बनायी जायेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गतिविधियों के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, ग्राम पंचायत संकुलों का गठन, संभागीय और जनपद स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन हो चुका है। जिला स्तरीय निगरानी और समीक्षा समितियों का गठन किया गया है।

अभियान में गाँवों के स्वच्छता प्लान, जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार, जलाभिषेक कार्यक्रम की तैयारी, गाँवों में गरीबी उन्मूलन की दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसे कार्यक्रम, मनरेगा में किये जाने वाले कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का चयन, गाँव को खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का अभियान, ग्रामीण विकास के विभिन्न योजना के नये हितग्राहियों की पहचान करने, महिलाओं का स्वस्थ्य परीक्षण, बच्चों में कुपोषण के प्रति जागरूकता लाने, कृषि ग्राम सभाओं का आयोजन जैसी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी।

कृषि महोत्सव 15 अप्रैल से

ग्रामोदय अभियान के शुभारंभ के एक दिन बाद 15 अप्रैल से कृषि महोत्सव की भी शुरूआत हो रही है। पाँच वर्ष में किसानों की आमदनी दुगनी करने, खेती के नये तरीकों की जानकारी देने, माँग के अनुरूप कृषि उपज की बोनी करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने, जैविक खेती को अपनाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने जैसी गतिविधियाँ संचालित की जायेगी। पूरे प्रदेश में 600 से ज्यादा कृषि क्रांति रथ किसानों को जागरूक बनायेंगे। इन कृषि क्रांति रथों के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकी की जानकारी और परामर्श दिया जायेगा। सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा।

कृषि महोत्सव में ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला बनायी गई है। हर जिले में कृषि मेलों का आयोजन किया जायेगा। कृषि संबंधी और किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, पशुपालन एवं सहकारिता, उद्यानिकी, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण विभागों से समन्वय स्थापित किया गया ताकि तत्काल इनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

आधार नहीं तो जून के बाद राशन नहीं मिलेगा

खाद्य आयुक्त द्वारा सौ फीसदी आधार दर्ज करवाने के निर्देश

भोपाल। खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने जिले के सभी खाद्य अधिकारियों को हितग्राहियों के सौ फीसदी आधार दर्ज करवाने के निर्देश दिये हैं।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार पंजीयन करना जरूरी हैं। आधार पंजीयन नहीं होने की स्थिति में भविष्य में राशन नहीं मिलेगा। आधार पंजीयन को 30 जून 2017 के बाद अनिवार्य कर दिया गया हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीएस के उपभोक्ता हितग्राही अपने परिवार के सदस्यों के आधार और अपने राशन कार्ड को नजदीकतम पीडीएस दुकान पर पहुँचकर पीओएस मशीन के माध्यम से आधार की सीडिंग समय पर कराना सुनिश्चित करें। आयुक्त खाद्य श्री पोरवाल ने विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह विभागीय अमले को गतिशील बनाकर सौ फीसदी आधार पंजीयन करवाये। शासकीय उचित मूल्य दुकान पर ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के आधार का पंजीयन नहीं हुआ है उन्हें सूचित करें और आधार पंजीयन करवाये। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरी गंभीरता से करें।

आयुक्त खाद्य ने पीडीएस उपभोक्ता हितग्राहियों से भी भविष्य में राशन नहीं मिलने की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार सार्वजनिक दुकान पर जाकर पंजीयन करवाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

आयोग की अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा होगी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी, उपाध्यक्ष श्री विभीषण सिंह और आयोग के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण गोदानी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आयोग की विभिन्न अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिये एजेन्सी बनाई जायेगी। आयोग की अनुशंसाओं पर विभिन्न विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन किया जाये। वृद्धजनों के लिये चल रहे डे-केयर सेंटरों को आनंद विभाग की गतिविधियों से जोड़ा जाये।

आयोग के अध्यक्ष श्री धर्माधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा 40 विभाग से संबंधित 488 अनुशंसाएँ की गईं थी, जिनके आधार पर विभागों द्वारा 434 आदेश जारी किये गये हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग गठित किया गया है। आयोग द्वारा प्रदेश के श्रेष्ठ वृद्धाश्रमों और डे-केयर सेंटरों को पुरस्कृत किया गया है। आयोग द्वारा भरण-पोषण अधिनियम के संबंध में कार्यशाला की गई तथा डे-केयर सेंटरों का राज्य-स्तरीय सम्मेलन किया गया। आयोग की विशेष पहल पर वृद्धाश्रमों के 403 वृद्धजन को सिंहस्थ स्नान कराया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को आयोग की अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों की संकलन पुस्तिका भी सौंपी गई। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल तथा आयुक्त सामाजिक न्याय श्रीमती नीलम शमी राव भी उपस्थित थीं।

समाधान योजना अब 30 अप्रैल तक

भोपाल। मध्य-पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में समाधान योजना अब 30 अप्रैल तक पुनः लागू की गई है। योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन और शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले निम्न दाब घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे।

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

जिलों में मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई शुरूआत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के केन्द्र के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के अन्य 48 जिलों में भी आज योजना के केन्द्रों की शुरूआत हुई। विभिन्न जिलों में योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री-परिषद के सदस्यों, विधायकों एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों ने किया।

योजना में सभी जिला मुख्यालय पर एक रसोई केन्द्र के जरिये मात्र 5 रुपये में दीनदयाल थाली जरूरतमंदों को उपलब्ध करवायी जायेगी। एक केन्द्र पर अधिकतम 2000 लोगों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। बड़े शहरों में आवश्यकतानुसार एक से अधिक रसोई केन्द्र भी संचालित किये जा सकेंगे। रसोई की थाली में 4 रोटी, एक सब्जी और दाल उपलब्ध होगी। यह रसोई स्मार्ट किचन में अत्याधुनिक मशीनों से तैयार की जायेगी। रसोई केन्द्र पर भोजन का समय सुबह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। खाद्यान्न की व्यवस्था एक रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान से होगी और नगर निगम अथवा नगरीय निकाय निःशुल्क पानी, बिजली प्रदाय करेंगे। योजना की मॉनटरिंग जिला-स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति करेगी। समिति में शासकीय अधिकारियों के अलावा अनाज व्यापारी संघ तथा सब्जी मण्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य रहेंगे।

दमोह- वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने जिला मुख्यालय पर योजना की शुरूआत की। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों के साथ सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को भी प्राथमिकता दी है। शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का टी.व्ही. पर लाइव प्रसारण देखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना का आगे चलकर विस्तार किया जायेगा। योजना को वृद्धाश्रम और अस्पतालों से भी जोड़ा जायेगा। श्री मलैया ने रेडक्रॉस समिति की ओर से वॉटर-कूलर देने की भी घोषणा की।

शिवपुरी- खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने जिला मुख्यालय पर योजना का शुभारंभ किया। मौजूद नागरिकों ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री के संदेश को सुना। जिला कलेक्टर ने बताया कि मंगलम स्वयंसेवी संस्था ने योजना को चलाने की जिम्मेदारी ली है।

रीवा- रीवा में योजना का शुभारंभ उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की उपस्थिति में हुआ। उद्योग मंत्री ने रसोई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज का कोई व्यक्ति भूखे पेट न रहे। श्री शुक्ल ने कहा कि योजना का जल्द ही विस्तार किया जायेगा। कार्यक्रम में विधायक श्री दिव्यराज सिंह, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

खण्डवा- स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने खण्डवा में पार्वतीबाई धर्मशाला में योजना का शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कम कीमत पर पौष्टिक आहार की थाली मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि योजना का विस्तार अस्पतालों में भी किया जायेगा। विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा और खण्डवा महापौर श्री सुभाष कोठारी भी मौजूद थे।

सिंगरौली- जिला मुख्यालय पर योजना का शुभारंभ सामुदायिक भवन बैढन में विधायक श्री रामलल्लू बैस ने किया। प्रारंभ में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित किया गया। महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार ने कहा कि योजना से गरीब व्यक्ति का पेट भर सकेगा। समाज-सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री अमित द्विवेदी ने 1100 रुपये और नगर निगम सफाई कर्मचारी बैढन की ओर से 2100 रुपये की राशि दिये जाने की घोषणा की गयी।

उज्जैन- योजना का शुभारंभ उज्जैन के नानाखेड़ा बस-स्टेण्ड पर हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण को सुना गया। उज्जैन महापौर श्रीमती मीना जोनवाल ने योजना की व्यवस्था की जानकारी दी।

आगर-मालवा- जिला मुख्यालय पर योजना का शुभारंभ विधायक श्री गोपाल परमार ने किया। विधायक श्री मुरलीधर पाटीदार ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा प्रत्येक गरीब व्यक्ति की मदद करना है। अतिथियों ने रसोई-घर में भोजन बनाने की प्रक्रिया और बर्तन धोने के स्थानों का भी निरीक्षण किया।

नरसिंहपुर- जिला अस्पताल परिसर में योजना का शुभारंभ हुआ। विधायक श्री जालम सिंह पटेल ने श्रम करने वाले गरीबों और जरूरतमंदों को 5 रुपये में सस्ता, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त भोजन परोसा।

खरगोन- योजना का शुभारंभ विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार की उपस्थिति में हुआ। निस्सहाय एवं निर्धन नागरिकों को 5 रुपये की राशि पर भरपेट भोजन परोसा गया।

बड़वानी- नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कोकिला पटेल की अध्यक्षता में योजना का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर ने बताया कि रसोई केन्द्र पर भोजन बनाने के सभी संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं।

झाबुआ- जिला मुख्यालय पर योजना का शुभारंभ हुआ। योजना के लिये रियायती दर पर 120 क्विंटल गेहूँ और 30 क्विंटल चावल उपलब्ध करवाया गया।

विंध्य व्यापार मेला उद्यमियों और कलाकारों को पहचान दिलाने का जरिया बना

भोपाल। वाणिज्य-उद्योग तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विंध्य व्यापार मेला उद्यमियों और कलाकारों को पहचान दिलाने का जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि इसका तीसरा सफलतम साल सांस्कृतिक एंव व्यावसायिक गतिविधियों को मंच देने में कारगर सिद्ध होगा। श्री शुक्ल शुक्रवार की शाम रीवा में विंध्य महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे।

श्री शुक्ल ने कहा कि महोत्सव से विंध्य तथा रीवा क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि हुई है। यह कार्यक्रम सभी को आनंद में सराबोर करने का अच्छा जरिया बन गया है। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में विभिन्न महोत्सव होते थे, तभी विंध्य महोत्सव की ओर ध्यान गया। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष विंध्य महोत्सव रीवावासियों के लिये एक बड़ी सौगात का काम करता है।

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत वर्ष व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण किया था। व्हाइट टाइगर सफारी अब देश-दुनिया में पहचान बन गया है। श्री शुक्ल ने कहा कि इस वर्ष के विंध्य महोत्सव के दौरान नवीन कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण होगा। अगले वर्ष विंध्य महोत्सव के दौरान राजकपूर ऑडिटोरियम का लोकार्पण प्रस्तावित है।

कमिश्नर श्री एस.के. पाल ने अपेक्षा की कि, विंध्य व्यापार मेला उद्यमियों, व्यापारियों को अच्छा व्यवसाय देगा। कलेक्टर श्री राहुल जैन ने विंध्य महोत्सव की जानकारी देते हुए कहा कि, महोत्सव से लोगों में नई ऊर्जा का संचार होने के साथ ही व्यवसाइयों के लिए भी यह उपयोगी बन गया है।

रेवांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री गजेंद्र शर्मा ने कहा कि महोत्सव मील का पत्थर है। उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने अभिनेत्री सुश्री लवीना टंडन को प्रतीक चिंह भेंट कर सम्मानित किया।

नर्मदा सेवा मिशन गठित

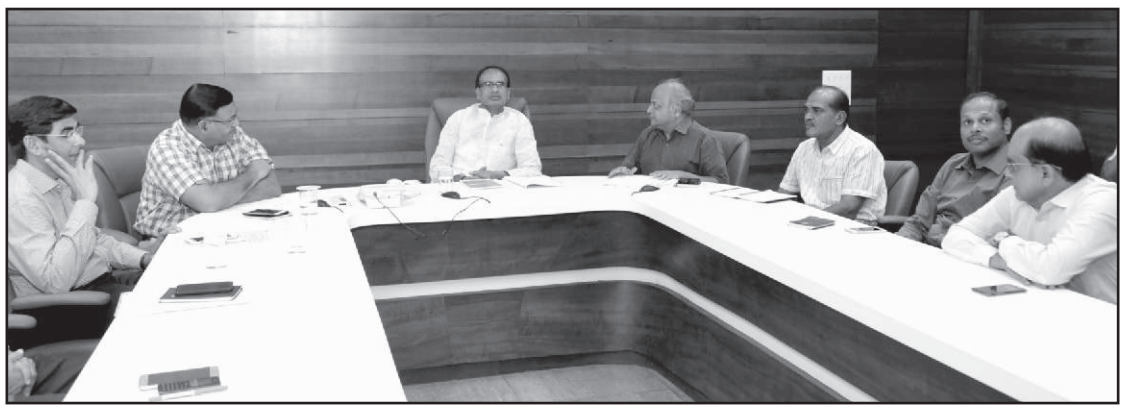

भोपाल। राज्य शासन ने नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये नर्मदा सेवा मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मिशन के संचालक अपर मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी होंगे। मिशन संचालक की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन समिति मिशन कार्य की सतत मॉनीटरिंग करेगी। प्रमुख सलाहकार अथवा सलाहकार राज्य योजना आयोग मिशन समन्वयक होंगे। सदस्यों में अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास और किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, पर्यावरण, पर्यटन, नगरीय विकास तथा आवास, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, पशु पालन, ग्रामोद्योग, राजस्व, खनिज, संस्कृति, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभागों के प्रमुख सचिव, जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक, मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित 5 विषय-विशेषज्ञ और नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत स्वयं सेवी/समाज सेवी संगठनों के 5 प्रतिनिधि होंगे।

मिशन के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप/सहायक संचालक उद्यानिकी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, उप संचालक पशुपालन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, उप/सहायक संचालक मत्स्य पालन विभाग, जिला खनिज अधिकारी, जिले के समस्त स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के संभागीय अभियंता, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के उप संचालक, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक, जिला योजना अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी और जिला कलेक्टर द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत स्वयंसेवी/समाजसेवी संगठनों के 5 प्रतिनिधि जिला समिति में सदस्य होंगे।

नर्मदा सेवा मिशन के कार्यों में वृक्षारोपण के माध्यम से तटीय क्षेत्र का संरक्षण, उन्नत स्वच्छता प्रबंधन, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्व%छता प्रबंधन, जल संग्रहण और नदी कछार क्षेत्र का विकास, प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन, जैविक खेती और गुड एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेस को प्रोत्साहन, संवेदनशील एवं स्वच्छ कृषि का विकास, नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन को आजीविका से जोड़ना, नदी संसाधनों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित करना, नदी क्षेत्र में स्वस्थ पारिस्थिकीय तंत्र का विकास करना, नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समाज की क्षमता वर्धन और सहभागिता सुनिश्चित करना और तटीय क्षेत्र में नशामुक्त समाज का निर्माण शामिल है।

मिशन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों का मूल्यांकन और समन्वय भी करेगा। मिशन के कार्यों में तटीय क्षेत्र में वानस्पतिक आच्छादन और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये निजी एवं शासकीय भूमि में वृक्षारोपण के लिये कार्य, स्वच्छ जीवन शैली विकसित करना, कृषि की आधुनिक पद्धति के कारण नदी एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर वैकल्पिक कृषि के विकास जैसे जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रदूषण के कारकों की पहचान कर उनका निवारण, नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन में आजीविका सुनिश्चित करते हुए समाज की सहभागिता बढ़ाना, नवीनतम तकनीकों का विकास, अनुसंधान एवं अंगीकरण, नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना शामिल होगा।

इसके अलावा मिशन के कार्यों में नर्मदा नदी के अस्तित्व की चुनौतियों को कम करने की दिशा में सतत प्रयास, नर्मदा नदी के संरक्षण वानस्पतिक एवं जल संरक्षण की प्राचीन पारम्परिक पद्धति का संकलन एवं दस्तावेजीकरण, नर्मदा कछार में जैव विविधता के संरक्षण के लिये शासकीय संस्थानों द्वारा किये जा रहे कार्यों को गति देना, स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों की शासन के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना, समाज के सभी वर्गों को नदी के संरक्षण के प्रति साक्षर करने के लिये नर्मदा सेवा केन्द्रों अथवा नर्मदा ज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नर्मदा संरक्षण के कार्यों से जोड़ना, तटीय क्षेत्र में धार्मिक परिवेश की पवित्रता बनाये रखने के लिये काम करना, संरक्षण में शासन के साथ समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना, नदी संरक्षण के लिये अनुदान राशि स्वीकार करना, सामाजिक सहभागिता के लिये नदी महोत्सव आदि विभिन्न महोत्सव के आयोजन के लिये संबंधित विभागों और संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना, तटीय क्षेत्र में स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करना और ऐसे सारे कार्य, जो मिशन के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है, शामिल हैं।

नेशनल लोक अदालत में 851 मामले निराकृत

पक्षकारों को लगभग 4,47,09,088 रुपये के मुआवजे एवं समझौता राशियाँ वितरित

भोपाल। नेशनल लोक अदालत में 851 सिविल एवं दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण हुआ। कुल 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा की मुआवजा और समझौता राशि निर्धारित कर लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय के दीवानी, दाण्डिक, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, प्रीलिटिगेशन, लोक उपयोगी सेवाओं संबंधी, नगर पालिका निगम अधिनियम एवं दुर्घटना दावा सहित विद्युत अधिनियम के प्रकरण की सुनवाई हुई। प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर किया। कुल 1415 पक्षकार लाभान्वित हुए।

श्री शैलेन्द्र शुक्ला जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा अदालत का उदघाटन किया गया। जिला न्यायालय की 57 खण्डीपीठों तथा जिला न्यायालय के अलावा अन्य खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों ने कुल 851 प्रकरणों का निराकरण किया।

कुल 4,47,09,088 रुपये के अवार्ड पारित कर प्रकरणों का सुलह समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हुआ। ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी से अवार्ड राशि रुपये 4,50,000 का चेक मौके पर ही दिलाया गया। कुटुम्ब न्यायालय में भी जटिल मामलों में राजनामा के आधार पर पीठासीन अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय श्री विनोद भारद्वाज ने दम्पत्ति का परिवार टूटने से बचाया।

प्रीलिटिगेशन पीठ द्वारा न्यायालय में विवाद आने के पूर्व ही पक्षकारों में आपसी समझौता कराकर कुल 291 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें 77,52,630 रुपये की राशि के मामलों में निराकरण हुआ।

मध्यप्रदेश 8 खनिज सम्पन्न राज्य में से एक

भोपाल। खनिज सम्पदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र के 8 खनिज सम्पन्न राज्य में से एक है। प्रदेश में प्रमुख रूप से 8 प्रकार के खनिज पाये जाते हैं। हीरा उत्पादन में मध्यप्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ ताम्र अयस्क और मेग्नीज के उत्पादन में देश में पहला स्थान प्राप्त है। इसके अलावा प्रदेश का रॉक-फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयले एवं चूना पत्थर के उत्पादन में स्थान चौथा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आवास गारंटी अधिनियम के नियम बनाने के दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास गारंटी अधिनियम के अमल के लिये इसी माह के अंत तक नियम बनाने के निर्देश दिये हैं। यहाँ मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने पात्र लोगों को आवासीय सुविधा देने के लिये रोडमेप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निश्चित समय-सीमा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों की सूची भी तैयार कर लें।

बैठक में बताया गया कि अगले साल तक सभी शहरों में शहरी गरीबों के लिये 5 लाख घर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके लिये विस्तृत कार्य-योजना तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण पर करीब 25 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा। इस योजना में 2 लाख 45 हजार आवास की स्वीकृति मिल गई है। अब तक 35 हजार 500 आवास पात्र शहरी गरीबों को दिये जा चुके हैं। नगर उदय अभियान में तीन लाख शहरी हितग्राहियों को आवास के लिये अधिकार-पत्र दिये जा चुके हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्वदेशी गौ नस्ल संरक्षण-संवर्धन के लिये प्रदेश की 15 गौ-शाला और 150 गांव का चयन

आईटीसी और बाएफ ने भोपाल में किया कार्यक्रम का शुभारंभ

भोपाल। आईटीसी और बाएफ ने इंदौर, उज्जैन और सीहोर की 15 गौ-शाला और उनके आसपास के 150 गाँवों का चयन स्वदेशी गौ नस्ल संरक्षण और संवर्धन के लिए किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन विभाग के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुउत्पादित गायों के संरक्षण-संवर्धन के साथ उनको उत्पादन के योग्य बनाना, स्वदेशी गौ नस्ल संरक्षण-संवर्धन के साथ गौ-शाला को जर्म प्लाज्मा एवं रिसोर्स सेन्टर की तरह विकसित कर उन्नत देशी गौ नस्लों का गौ-संवर्धन, गैर वर्णात्मक पशुओं का अच्छी स्वदेशी दुधारू-गिर, साहीवाल आदि से प्रजनन कर नस्ल सुधार और जलवायु परिवर्तन के साथ अपर्याप्त उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए स्वदेशी दुधारू नस्ल का संरक्षण करते हुए उनकी संख्या बढ़ाना है।

नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. डी.के. सदाना ने 10 पी मॉडल के माध्यम से, बाएफ पुणे के कार्यक्रम निदेशक डॉ. आलोक जुनेजा ने देश-विदेश में प्रचलित सफल गौ- नस्ल संरक्षण और संवर्धन तकनीक पर जानकारी दी। डॉ. जुनेजा ने बताया कि नवीन तकनीक से गाय के गर्भाधान के 18वें दिन ही गाभिन होने का पता लगाया जा सकता है। इससे उसकी अच्छी देख-भाल होने से स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. महैया ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वदेशी गौ-नस्ल संरक्षण एवं संवर्धन योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में आईटीसी के मिशन सुनहरा कल परियोजना में बाएफ (भारतीय एग्रो फाउण्डेशन) द्वारा उत्पन्न गिर स्वदेशी गाय का पालन कर दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिये हाल ही में रा%य शासन द्वारा गोपाल पुरस्कार से पुरस्कृत किसान श्री राजाराम और श्री गजेन्द्र सिंह ने अपने अनुभव साझा किये। उन्होंने जैविक खाद और गौ-मूत्र से विभिन्न प्रकार की औषधि तैयार करने की भी जानकारी दी।

कार्यक्रम में दिव्य %योति जागृति संस्थान पंजाब के स्वामी विद्यानंद, क्षेत्रीय प्रबंधक आईटीसी श्री गिरीश मोहन, चयनित गौ-शाला प्रबंधन समिति सदस्य, बाएफ के तकनीकी पदाधिकारी, आरजीएम, एन.आर.एल.एम. और आरटीसी के विभिन्न संस्थान के अधिकारी मौजूद थे। बाएफ के मुख्य कार्यक्रम संयोजक श्री एस.के. पाण्डेय ने आभार माना।

लालिमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन ने **लालिमा योजना** के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग की भागीदारी वाली कार्यकारी समिति का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव वन, आयुष, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला-बाल विकास, आदिम-जाति कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ, आयुक्त महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक, समिति के सदस्य होंगे।

आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा समिति के सदस्य सचिव बनाये गये हैं। कार्यकारी समिति अभियान का मार्गदर्शन, नीतिगत निर्णय, अंतर्विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण का काम करेगी और क्रियान्वयन के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश देगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठक होंगी। इसमें अभियान के संचालन के निर्देश तथा जिला एवं विकासखण्ड-स्तर पर क्रमश कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा क्रियान्वयन की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जायेगा।

प्रदेश में बच्चों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं एनीमिया के उन्मूलन के लिये जन-जागरूकता लाने **लालिमा योजना** चलायी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को राज्य वन विकास निगम ने 111 करोड़ 44 लाख का चेक सौंपा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज यहाँ मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा राज्य शासन को देय लाभांश राशि 111 करोड़ 44 लाख रूपये का चेक सौंपा गया। इस मौके पर वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, निगम के अध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा और अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निगम की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। बताया गया कि निगम द्वारा पहली बार 100 करोड़ रूपये से अधिक का लाभांश दिया गया है। निगम लाभ की स्थिति में हैं तथा वन विभाग के माध्यम से लगभग 40 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है।

इस अवसर पर निगम के प्रबंध संचालक श्री रवि श्रीवास्तव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला भी उपस्थित थे।

नि:शक्त विवाह योजना

भोपाल। नि:शक्त विवाह योजना में राज्य शासन ने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दुगनी कर दी है। अब हितग्राहियों को आधी राशि नगद तो आधी राशि का सावधि जमा प्रमाण पत्र मिलेगा। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन ने नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत मिलने वाले 25 हजार के लाभ को बढ़ाकर 50 हजार तथा 50 हजार मिलने वाले लाभ को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसमें से आधी राशि जहां हितग्राही के बैंक खाते में नगर जमा होगी वही आधी राशि का 5 वर्ष का सावधि जमा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में नागरिकों को मिलेगी सभी बुनियादी सुविधाएँ

वित्त मंत्री श्री मलैया द्वारा दमोह 850 से अधिक आवासीय भवनों का भूमि-पूजन

भोपाल। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले आवासीय क्षेत्र में नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति का अपना आवास होगा। वित्त मंत्री श्री मलैया दमोह में अटल आश्रय योजना में 867 आवास और 50 दुकानों के भूमि-पूजन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। आवास योजना की लागत 64 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि दमोह में सड़कों का विकास, बायपास निर्माण, रेलवे ओव्हर ब्रिज और अन्य विकास कार्य तेजी से करवाये जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि दमोह जिले में विकास के सभी कार्य तय समय-सीमा में पूरे किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आज जिन आवासीय भवनों का भूमि-पूजन हुआ है वहाँ उद्यान, स्कूल, अस्पताल सहित नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएँ दी जायेगी।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे ने अपने उदबोधन में कहा कि हाउसिंग बोर्ड वर्ष 2018 तक 25 हजार लोगों को मकान बनाकर देगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने तय किया है कि मार्च 2018 तक 7,500 ई.डब्ल्यू.एस. और 5,500 एलआईजी मकान तैयार करेगा। श्री मोघे ने कहा कि प्रदेश में 2200 एचआईजी और 2500 फ्लेट का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को सांसद श्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड 60 हेक्टेयर भूमि में आवास और दुकान तैयार कर रहा है। इनमें से मात्र केवल 58ई.डब्ल्यू.एस. का पंजीयन होना शेष रह गया है।

नर्मदा सेवा उप यात्रा को झण्डी दिखाकर रवाना किया

नमामि देवि नर्मदे-सेवा यात्रा में शामिल होने नरसिंहपुर जिले जा रही उप यात्रा को आज मंत्री श्री जयंत मलैया ने दमोह से झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में माँ नर्मदा भक्त, जन-प्रतिनिधि तथा पंचायत प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकमौजूद थे।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहाँ-जहाँ माँ नर्मदा का प्रवाह है, वहाँ यात्रा निकाली जा रही है। आज की रैली बरमान घाट जा रही है, उन्होंने कहा जहाँ मॉ नर्मदा नहीं है वहाँ से उप-यात्रा जा रही है। श्री मलैया ने कहा नर्मदा तट के 500-500 मीटर दोनों ओर पौध-रोपण किया जायेगा। निजी जमीन पर किसानों को पौध लगाने और उनेक संरक्षण के लिये राशि भी दी जायेगी। उन्होंने कहा सरकार की मंशा माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करना है। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा को भारी जन-समर्थन मिल रहा है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी 3 स्थान पर यात्रा में शामिल हुआ हूँ। आज जिला मुख्यालय के 13 मण्डल से नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में 75 वाहन से सेवक रवाना हुए।

मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में 75 प्रतिशत से अधिक अंक वाले विद्यार्थी पात्र होंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए पढ़ने के साथ खेलना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल अत्यंत जरूरी है। श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास में विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की खेल प्रतिभाओं को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के प्रकल्पों में सहयोग करना सरकार का कर्त्तव्य है। समाज के ऐसे हर प्रयास को सरकार का सहयोग मिलेगा। विद्याभारती सीमित संसाधनों में भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कारों के निर्माण का कार्य कर रही है। संस्था के प्रयासों में सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ इसकी रूपरेखा तैयार होगी। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य बच्चों में है।

उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बारहवीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। उनके पालकों की आय 6 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों का शासकीय, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि और निजी क्षेत्र के चिन्हित इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश होने पर उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण समय की जरूरत है। नर्मदा सेवा यात्रा नदी संरक्षण का अनुष्ठान है। आगामी दो जुलाई को नर्मदा के दोनों तट पर पौधरोपण किया जायेगा। इस दिन पौधे लगाकर इस अनुष्ठान में सहयोग के लिए उन्होंने विद्या भारती से अनुरोध किया।

श्री चौहान ने चैत्र-नवरात्र और नववर्ष की शुभकामनाएँ दी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों का आव्हान किया कि वे बेटियों के मान-सम्मान के प्रति संकल्पित हो। उनके प्रति शुद्ध और पवित्र दृष्टि रखें। बेटियों के प्रति सम्मान के भाव को प्रगट करते हुए उन्होंने बताया कि नर्मदा यात्रा के प्रारम्भ में कन्या के चरण धोकर, उसके जल को मस्तक से लगाते हैं। इससे उनमें नई शक्ति और ऊर्जा भर जाती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा विभाग में 50 तथा शेष विभाग (वन छोड़कर) में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। श्री चौहान ने स्वच्छता अभियान के प्रति संकल्पित होने का आव्हान किया तथा पदक विजेताओं को शुभकामनाएँ दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को श्री भागीरथ कुमरावत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हिन्दी भाषा की पाठ्य-पुस्तकों की भूमिका पर किया गया शोध-प्रबंध भेंट किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुँवर विजय शाह ने कहा कि शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसका दूरभाष क्रमांक सभी एक लाख 18हजार शासकीय शाला में अंकित रहेगा। शाला में उपस्थित नहीं होने वाले शिक्षक की जानकारी कोई भी प्रकोष्ठ को दे सकेगा। नियंत्रण प्रकोष्ठ मोबाइल फोन के माध्यम से शिक्षक की उपस्थिति की जानकारी लेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों में अतिथियों का स्वागत अब फूल-माला और पुष्प-गुच्छ से नहीं बल्कि उनका अभिनंदन पुस्तकें भेंटकर किया जायेगा। विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थी सभी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रावीण्य-सूची में आए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता संस्थान की पहचान है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश मिश्रा ने बताया कि एशियन स्कूल गेम्स हॉकी प्रतियोगिता होगी। फेडरेशन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन और खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए विद्या भारती को सम्मानित करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर भी उपस्थित थे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सह सचिव श्री मुक्तेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विद्या भारती ने देशभर में 180 से अधिक पदक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें मध्यप्रदेश के 16जिलों ने सहभागिता करते हुए स्वर्ण-17, रजत-28, कांस्य-57 कुल 102 पदक प्राप्त किए है। इस वर्ष 305 छात्र एवं 129 छात्राओं सहित कुल 434 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में सहभागिता की।

महिलाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने लागू होगी कौशल्या योजना

हर साल 2 लाख महिलाएँ होंगी प्रशिक्षित

भोपाल। प्रदेश में महिलाओं को रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष से कौशल्या योजना लागू की जा रही है। योजना में हर साल 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने बताया है कि योजना में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ चुकी महिलाएँ, ऐसी कामगार महिलाएँ जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण करवाना चाहती हैं और ऐसी कामगार महिलाएँ जो अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं, को प्राथमिकता दी जायेगी। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

महिलाओं को परिधान एवं गृह सज्जा, आटो मोबाइल्स, सौंदर्य प्रसाधन, केपिटल गुड्स, निर्माण, घरेलू काम-काज, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईवेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, आई.टी. सुरक्षा, टेलीकॉम, टूरिज्म एण्ड हास्पिटेलिटी एवं वित्त सेवा से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के आधार पर कौशल दक्षता के स्तर निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे, जिनके लिए रोजगार देने वाले सुनिश्चित रोजगार देने के लिए अनुबंध करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की उपस्थिति में एम.पी. एग्रो ने अटल बाल मित्र योजना के लिये 2.60 करोड़ का चेक सौंपा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यहाँ मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा महिला-बाल विकास विभाग को 2 करोड़ 60 लाख रूपये का चेक सौंपा गया। निगम द्वारा यह राशि कार्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत दी गयी है।

बताया गया कि यह राशि अटल बाल मित्र योजना के लिये दी गई है। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष श्री रामकिशन चौहान, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तथा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री एस.के.मिश्रा उपस्थित थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।